

अस्मधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 99] No. 99] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2011/ज्येष्ठ 19, 1933 DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2011/JYAISTHA 19, 1933

[रा.स.स.क्षे.दि. सं. 62 [N.C.T.D. No. 62

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जून, 2011

सं. फा. 6(26)/09-न्याय/702-707.—दिल्ली के उपरान्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, सुश्री शिफा जगलियान, जिनका नाम इस विभाग के दिनांक 17-2-2011 की अधिसूचना संख्या फा. 6/26/09-न्याय/एसयूपीटी लॉ/175-180 में कम संख्या 21 पर उल्लिखित था, की नियुक्ति को, उनकी अनिच्छा के कारण, दिल्ली न्यायिक सेवा में कार्यभार संभालने में असफल रहने पर निरस्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

तरुन सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th June, 2011

F. No. 6(26)/09-Judl./Suptlaw/702-707.—The Lt. Governor, Delhi in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to cancel the appointment of Ms. Shifa Jaglian, on account of her unwillingness to join the Delhi Judicial Services, whose name appears at Sl. No. 21 of this

Department's Notification No. F. 6(26)/09-Judl./Suptlaw/ 175-180 dated 17-2-2011.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secv.

राजस्व विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 9 जुन, 2011

सं एफ. 11(11)/रा.स्था./99/पार्ट फाइल/745.— सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 95 दिनांक 21-3-2011 के सन्दर्भ में श्रीमती नन्दिनी पालीवाल, आई. ए. एस. (ए.जी.एम.चू : 2003) ने दिनांक 28-3-2011 (पूर्वाह्न) को उपायुक्त (दक्षिण), जिला दक्षिण का कार्यभार संभाल लिया है, अत:,

> 1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की घारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमती नन्दिनो पालीवाल, आई. ए. एस. (ए.जी.एम.यू : 2003)/उपायुक्त, को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं।

- 2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 3(6) में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमती निन्दिनी पालीवाल, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.चू.: 2003)/उपायुक्त, को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लो में उपायुक्त के कार्यपालन हेतु शिक्तयां प्रदान करते हैं ।
- 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथाविस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम, 1887 की धारा 105 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्लोमती नन्दिनी पालीवाल, आई. ए. एस. (ए.जी.एम.यू: 2003)/उपायुक्त, को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधि नियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शिक्तयां प्रदान करते हैं।
- 4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1)(ए) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमती निन्दिनी पालीवाल, आई. ए, एस. (ए.जी.एम.यू. : 2003)/उपायुक्त को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्मत कलैक्टर की समस्त शिक्तयां प्रदान करते हैं।
- 5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तास्ति उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमती नन्दिनी पालीवाल, आई. ए, एस. (ए.जी.एम.यू.: 2003)/उपायुक्त, को जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।
- 6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग कंसोलिडेशन तथा प्रिवेंशन ऑफ फ्रगमेंटेशन अधिनियम, 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमती निन्दिनी पालीवाल, आई. ए, एस. (ए,जी.एम.यू.: 2003)/उपायुक्त, को जब तक वे राजस्य विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत बरोबस्त अधिकारी (चकवंरी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर. कुलदीप सिंह गंगर, अतिरिक्त सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 9th June, 2011

- F. No. 11(11)/Rev. Estt./99/P. File/745.—In pursuance of Services Department's Order No. 95 dated 21st March, 2011, Ms. Nandini Paliwal, IAS (AGMU: 2003) has joined as Deputy Commissioner (South), District South on 28th March, 2011 (F/N), Now, therefore,—
 - (i) In exercise of powers conferred by Section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Ms. Nandini Paliwal, IAS (AGMU: 2003)/Deputy Commissioner as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act to her so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
 - (ii) In exercise of powers conferred by Section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Ms. Nandini Paliwal, IAS (AGMU: 2003)/Deputy Commissioner to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
 - (iii) In exercise of powers conferred by Section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Ms. Nandini Paliwal, IAS (AGMU: 2003)/ Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
 - (iv) In exercise of powers conferred by Section 27(1)
 (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Ms. Nandini Paliwal, IAS (AGMU: 2003)/Deputy Commissioner, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the

Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

- (v) In exercise of powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Ms. Nandini Paliwal, IAS (AGMU: 2003)/ Deputy Commissioner all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- (vi) In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints Ms. Nandini Paliwal, IAS (AGMU: 2003)/Deputy Conmissioner and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer (Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act to him so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.

सं. एक. 1(36)/पंजी. शाखा/मुख्या./मंडली.आयु./
2010/141.—राज्य मंत्रालय की दिनांक 20 सितम्बर, 1950 की
अधिसूचना संख्या 124-जे और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की
दिनांक 7 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना का.आ. 2709 (सं. फा.
41/2/66-दिल्ली) द्वारा यथाआशोधित राज्य मंत्रालय की दिनांक 24
अगस्त, 1950 की अधिसूचना सं. 104जे के साथ पठित राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत्त पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908
का 16) की धारा 78 एवं 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस सरकार की
दिनांक 1-7-2010 की अधिसूचना सं फा. 01(36)/पंजी. शाखा/मु/
मंडल.आयु/2010/353 के अनुसार अधिसूचित प्रलेखों के पंजीकरण
हेतु पंजीकरण शुल्क एवं विविध शुल्क की तालिका में निम्नलिखित
संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त तालिका में,-

(i) बही-1 के संबंध में क्रम संख्या 1 पर मद के खंड (क)
 के सामने जैसांकि प्रथम कॉलम में उल्लिखित है, आरोप्य
 पंजीकरण शुल्क के उल्लेख करने संबंधी दूसरे कॉलम

से सम्बद्ध प्रविध्ि के लिए और सर्किल दर के अनुसार मूल्य की निश्चित प्रतिफल राशि का 1 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, अधिकतम 50,000 रुपये तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रविध्ट स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"सर्किल दर के अनुसार निश्चित प्रतिफल राशि या मूल्य का एक प्रतिशत, न्यूनतम एक हजार रुपये, जो भी अधिक हो।"

(ii) बही IV के संबंध में क्रम सं. 3 पर मद के स्थान पर, जैसांकि प्रथम कॉलम में उल्लिखित है, और आराप्य पंजीकरण शुल्क निम्नलिखित मदें और सम्बद्ध प्रविष्टियों का उल्लेख करने संबंधी दूसरे कॉलम में यथाउल्लिखित इसमें सम्बद्ध प्रविष्टि, प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वर्णन/विवरण	आरोप्य शुल्क
बही IV में अर्थात् सभी अन्य प्रलेखों के विविध पंजीकरण	1000 रुपये प्रति प्रलेख
(क) प्रतिफल संहित जीपीए	सर्किल दर के अनुसार निश्चित प्रतिफल राशि या मूल्य का एक प्रतिशत, जो भी अधिक हो

यह अधिसूचना जून 10, 2011 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

राजेश मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 1(36)/Regn. Br/HQ/Div.Com./2010/141.—
In exercise of the powers conferred by Sections 78 and 79 of the Registration Act, 1908 (16 of 1908) as applicable to the National Capital Territory of Delhi read with Ministry of States Notification No. 104-J dated the 24th August, 1950 as modified by the States Ministry's Notification No. 124-J dated the 20th September, 1950 and Ministry of Home Affairs, Government of India Notification No. 2709 (No. F. 4112/66-Delhi) dated the 7th September, 1966, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in the Table for Registration Fee and Miscellaneous Fee for Registration of Documents, notified vide this Government's notification No. F. 1(36)/Regn.Br/HQ/Div.Com./2010/353 dated 1st July, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said Table,-

(i) against clause (a) of Item at serial number 1 in relation to Book 1, as described in the first column, for the corresponding entry in the second column specifying the registration fee leviable and reading as "1 per cent of consideration amount set forth of value as per circle rate whichever is higher subject to maximum of Rupees 50,000", the following entry shall be substituted, namely:—

Subject to a minimum of Rupees one thousand, one per cent of the consideration amount set forth or the value as per the circle rate, whichever is higher."

(ii) for Item at serial number 3 in relation to Book IV, as described in the first column, and the corresponding entry relating thereto as described in the second column, specifying the registration fee leviable, the following Items and the corresponding entries shall be substituted, namely:—

Fee Leviable

(1)	(2)
In Book IV i.e. Miscellaneous registration of all other documents.	₹ 1000 for each
(1)	(2)
(a) GPA with consideration	One per cent of the consideration amount set forth or value as per circle rate whichever is higher.

This notification shall come into force w.e.f. June 10, 2011.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

> RAJESH MISRA, Spl. Inspector General (Registration)